



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 4 अगस्त, 1992/13 भाद्रपद, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 अगस्त, 1992

संख्या-एल० एस०जी०-बी० (15) 14/81.—फिंगरसक एस्टेट में दीपक गैस्ट हाऊस के नाम से जाना जाने वाला भवन तारीख 15-7-1992 की रात को गिरने के कारण 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कई अन्य घायल हुए थे ;

और जन साधारण उक्त घटना के कारणों की न्यायिक जांच की मांग कर रही है ;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि उक्त घटना की जांच के लिए, जोकि सार्वजनिक महत्व का मामला है, जांच आयोग की नियुक्ति अत्याधिक समीचीन और लोकहित में होगी ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश, की पूर्ण सहमति से, माननीय न्यायमूर्ति आर० बी मिश्रा,

लोकामुक्त, हिमाचल प्रदेश को, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उद्धरीकत घटना के सम्बन्ध में निम्नलिखित मामलों की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं :—

### टर्म्स आफ रेफरेंस

- (क) क्या उक्त भवन के निर्माण में नगर निगम शिमला द्वारा लागू कानून का कोई उल्लंघन हुआ है।
- (ख) इस घटना के क्या कारण थे तथा क्या इस घटना को बचाया जा सकता था।
- (ग) क्या ऐसे उल्लंघनों के मामले में, पानी व बिजली के कनेक्शन दिया जाना उचित है तथा इस निमित्त कोई अन्य कार्रवाई की जानी चाहिए।
- (घ) इस घटना के उपरान्त फिगामक एस्टेट में कोई अन्य घटना या घटनाएं सम्भावित हैं तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या-क्या उपाए करने आवश्यक हैं।
- (च) क्या जो निर्माण किया गया था वह विहित मापदण्डों के अनुसार था।
- (छ) क्या टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग इत्यादि द्वारा विहित मापदण्डों का दृढ़ता से पालन किया गया था।
- (ज) क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले उस भूमि (स्थान) के स्ट्राटा के बारे में किसी विशेषज्ञ की राय ली गई थी अथवा नहीं।
- (झ) क्या इस भवन की ऊंचाई विहित मापदण्डों के अनुसार थी।
- (ट) क्या वर्तमान में इस भवन के नीचे अथवा आस पास खुदाई का काम जारी था जिस की वजह से यह घटना घटी।
- (ठ) क्या इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम करने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन की आवश्यकता है, जिस से कि इस प्रकार की हानि रोकी जा सके।
- (ड) उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य कारण जो इस घटना का कारण बना।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि, की जाने वाली जांच मामले की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान म रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा (2)(3)(4) और (5) के उपबन्ध आयोग को लागू होंगे और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देते हैं कि धारा 5 की उप-धारा (2)(3)(4) और (5) में अन्तर्बिष्ट उपबन्ध आयोग को लागू होंगे।

आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा और आयोग ऐसे स्थानों का दौरा भी कर सकेगा, जो जांच को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

आदेश द्वारा,  
एस0 एस0 सिद्धू,  
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English Text of this Department notification No. LSG-B (15)14/81, dated 1-8-1992 as required under Article 348(3) of Constitution of India].

## LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 1st August, 1992*

No. LSG-B (15) 14/81.—Whereas due to collapse of the building known as Deepak Guest House in Fingask Estate on the night of 15-7-1992, 20 persons died and several others got injured;

And whereas general public is demanding judicial inquiry into the causes of said incident;

And whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that it would be more expedient and in public interest to appoint a Commission of Inquiry to inquire into the aforesaid incident which is a matter of public importance;

Now, therefore, Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952, with the prior consent of Lokayukta, Himachal Pradesh is pleased to appoint Justice R. B. Mishra, Lokayukta, Himachal Pradesh as the Commission of Inquiry and to inquire into and report on the following matters in relation to aforementioned incident within 3 months from the date of publication of this notification in Rajpatra, H. P.:—

- (a) As to whether there was any violation of laws enforced by the Municipal Corporation, Shimla in the construction of said building.
- (b) What were the reasons of this incident and as to whether this incident could have been averted.
- (c) As to whether in the cases of such violations, it will be proper to grant water and electricity connections and any other action should be taken in this respect.
- (d) As to whether any other incident or incidents are apprehended in Fingask Estate after this incident and what measures are necessary to prevent such incidents in future.
- (e) As to whether the construction work done was in accordance with the norms prescribed.
- (f) As to whether norms prescribed by the Town & Country Planning Department etc. were strictly complied with.
- (g) As to whether any expert opinion about the strata of that land (site) was obtained before starting construction work.
- (h) As to whether the height of this building was in accordance with the norms prescribed.
- (i) As to whether excavation work was going on beneath the building and its surroundings due to which the incident occurred.

(j) As to whether there is any necessity to amend the existing laws to prevent such incidents in order to prevent such loss.

(k) In addition to above any other cause which might have led to this incident.

Further, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that having regard to the nature of inquiry to be conducted and other circumstances of such case, the provisions of sub-section (2) (3) (4) and (5) of section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952 should be made applicable to the Commission and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 5 of the aforesaid Act, Governor, Himachal Pradesh is pleased to direct that the provisions contained in sub-section (2) (3) (4) and (5) of section 5 shall apply to the Commission.

The Commission shall have its Headquarters at Shimla and may also visit such places as may be necessary in the furtherance of the inquiry.

By order,

S. S. SIDHU, I.A.S.,

*Financial Commissioner-cum-Secretary.*